



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2009/आषाढ़ 26, 1931

No. 245]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2009/ASADHA 26, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2009

विषय : भारत में जापान, यूरोपीय संघ, नाइजीरिया तथा थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 6-हेक्जेनलेक्टम के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा—जांच की समाप्ति ।

फा. सं. 15/31/2008-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 एवं सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने यह जांच करने के लिए कि क्या जापान, यूरोपीय संघ, नाइजीरिया तथा थाइलैंड (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) से 6-हेक्जेनलेक्टम (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) पर शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की थी । इस जांच की शुरुआत 2006 की डब्ल्यूपी सं. 16893 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर आधारित थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का अभिमत था कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है ।

2. और यतः उपर्युक्त जांच शुरुआत के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने दिनांक 16 जून, 2009 की अधिसूचना सं. 66/2009-सी.शु. द्वारा संबद्ध देशों से भारत में किए गए आयातों पर पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क बढ़ा दिया था ।

3. प्राधिकारी ने दिनांक 22 अप्रैल, 2009 की निर्णायक समीक्षा जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति तथा आवेदन पत्र संलग्न करते हुए दिनांक 27 अप्रैल, 2009 के पत्र के माध्यम से घरेलू उद्योग से निर्धारित रूप व तरीके से सुसंगत सूचना प्रस्तुत करने एवं वर्तमान समीक्षा के संबंध में अपने विचारों से प्राधिकारी को अवगत कराने का अनुरोध किया था, ताकि प्राधिकारी आगे जांच संबंधी कार्यवाही कर सकें । घरेलू उद्योग ने अब एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया है कि वह पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए अब आवेदन नहीं कर रहे हैं और वर्तमान जांच की कार्यवाही को और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

4. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क (5) में उपबंधित है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा, बशर्त कि केन्द्र सरकार का समीक्षा में यह अभिमत हो कि ऐसा शुल्क समाप्त होने की परिणति पाटन व क्षति के जारी रहने व उसकी पुनरावृत्ति में होगी । प्रस्तुत मामले में घरेलू उद्योग ने लिखित अनुरोध किया है कि जांच की कार्यवाही और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है, अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात से संबंधित समीक्षा जांच को एतद्वारा समाप्त करते हैं और सिफारिश करते हैं कि जापान, यूरोपीय संघ, नाइजीरिया तथा थाइलैंड से 6-हेक्जेनलेक्टम के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाए ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2009

Subject : Sunset Review of anti-dumping investigations concerning imports of 6-Hexanelactum from Japan, European Union, Nigeria and Thailand into India—Termination of Investigation.

F. No. 15/31/2008-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof, the Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, had initiated a Sunset Review investigation *vide* Notification dated the 22nd April, 2009 to examine whether the expiry of duty on 6-Hexanelactum (hereinafter referred to as subject goods), from Japan, European Union, Nigeria and Thailand (hereinafter referred to as subject countries), is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The investigation was initiated based upon the directions of Hon'ble High Court of Delhi in W. P. No. 16893 of 2006 where the Hon'ble High Court held that sunset review is mandatory.

2. And whereas, pursuant to the above initiation, the Central Government, *vide* Notification No. 66/2009-Customs, dated 16th June, 2009 extended Anti-Dumping Duty, already in place on the imports of subject goods from subject countries into India.

3. The Authority requested the domestic industry *vide* letter dated 27th April, 2009, enclosing a copy of the sunset review investigation initiation notification dated 22nd April, 2009 and application proforma, to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority relating to the present review to enable the Authority to proceed further with the investigation. The domestic industry has now made a written submission that they are not making an application for extension of anti-dumping duties and have further requested that present investigation need not be pursued further.

4. Section 9A (5) of the Customs Tariff Act provides that the anti-dumping duty imposed shall, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In the instant case, the domestic industry having made a written request that the investigation need not be pursued further, the Authority hereby terminates the subject review investigation on import of subject goods from subject countries and recommends that the anti-dumping duties on the imports of 6-Hexanelactum from Japan, European Union, Nigeria and Thailand into India, may be discontinued.

R. GOPALAN, Designated Authority